विचार बिन्दु

कस्तूरी को अपनी मौजूदगी कसम खाकर सिद्ध नहीं करनी पड़ती;
गुण स्वयं ही सामने आ जाते हैं। –अज्ञात

चीते को फिर बसाने के प्रयोग से राजस्थान वंचित रह गया

वन्य जीवों में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता भारत में 1952 में लुप्त होना अधिकृत रूप से घोषित कर दिया गया था। उसे इस देश की धरती पर फिर से बसाने के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया से आठ चीते लाए गये हैं। इनमें पांच मादा और तीन नर चीते हैं। इन चीतों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉलर लगे हैं, जो नामीबिया से इन्हें लाने से पहले ही इन पर लगा दिए गए हैं। हालांकि यह प्रयोग विवादास्पद है कि लाए गये चीते नई धरती, नए वातावरण और नई पारिस्थितिकी में अपने को ढाल कर अपनी संतति को बढ़ा सकेंगे जिससे यहां के वनों में चीतों उनकी उपस्थिति फिर से वैसी हो सके जैसी कभी हुआ करती थी। यह भी सच है कि जब हम किसी एक जीव को लुप्त होने से बचाते हैं तो पूरी कायनात को बचाते हैं। प्रकृति का सारा पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार बना हुआ है जिसमें सम्पूर्ण चर-चराचर जगत एक अनदिखे सूत्र में पिरोया हुआ है। लाखों वर्षों के पृथ्वी के इतिहास में अनेक बार प्रकृति ने विध्वंस भी किया है जिसमें जीवों की प्रजातियां पूरी तरह नष्ट हो गई। परंतु प्रकृति ने हर बार फिर से जीवन को प्रस्फुटित किया और थामा। प्रकृति की अपनी प्रकृति है किन्तु विकसित मानव अब उसमें हस्तक्षेप करने लगा है जिससे जीवों की प्रजातियां नष्ट हो कर लुप्त हो रही है। यह मानवीय हस्तक्षेप ही था जिसने चीतों को भारत की धरती से लुप्त किया। यह हस्तक्षेप आप आदमी ने नहीं किया। यह राजा, महाराजाओं तथा उनके बराबरी वालों ने किया जिन्होंने वन्य प्राणियों को मारने को अपना मनोरंजन का साधन आखेट बना लिया। भारत में अफ्रीकी नस्ल के चीतों को जिस जहां बसाया जाने की कोशिश हो रही है, उसी मध्यप्रदेश की एक रियासत कोरिया में देश में आखिरी बचे एशियाई चीते मारे गए थे। कोरिया अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। इसी कोरिया रियासत के राजमहल के एक कमरे में, मारे गए इन अंतिम चीतों के सिर टंगे हुए हैं। पुराने दस्तावेज़ बताते हैं कि दिसंबर 1947 में कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंहदेव ने अपनी रियासत के रामगढ़ इलाक़े में तीन चीतों का शिकार किया था। उसके बाद भारत में एशियाई चीतों के कोई प्रमाण नहीं मिले और भारत सरकार ने 1952 में चीतों को देश में विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया और यह वन्य पशु इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह अनोखा संयोग है कि चीते के इतिहास का अंतिम पन्ना, अविभाजित मध्यप्रदेश में लिखा गया तो इसके पुनर्वास का नया अध्याय भी इसी प्रदेश से शुरू हो रहा है। राजस्थान के अनेक लोगों को मलाल है कि यह नया अध्याय उनका प्रदेश भी लिख सकता था मगर ऐसा न हो सका क्योंकि राजनीति के बड़े मसाइलों के द्वन्द्व में व्यस्त शासन के कर्ता-धर्ताओं के पास ऐसे मुद्दों पर सोचने, समझने और कुछ करने की फुर्सत ही कहां है। बहुत से वन विशेषज्ञ भी इससे सहमत नहीं थे।

वन्य प्राणी विशेषज्ञों को याद है कि विलुप्त चीते को भारत वापस लाने का विचार जब 2008-2009 में पहली बार हुआ तब दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य अधिकारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी जिसमें चीतों को भारत में पुन: बसाने की क्षमता वाले इलाकों का पता लगाने के लिए साइट सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। फिर देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने तीन राज्यों – राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की पहचान की थी जहां चीतों की आबादी को फिर से बसाया जा सकने की गुंजाइश थी। इसमें सबसे ऊपर राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज़ का 4,220 वर्ग किमी का इलाका था तथा दूसरे स्थान पर 748 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला मध्यप्रदेश का कुनो पालपुर था। लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में इस परियोजना की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। फिर जब इस पर से अदालती रोक हटी तब 2020 से फिर हलचल शुरू हुई। दो साल पहले फिर प्रयास हुए थे कि चीते आयें तो वे राजस्थान के इलाकों में बसें। राजस्थान के अधिकारियों ने तब कहा भी था कि राज्य सरकार चीता लाने की संभावना तलाशने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। मगर ऐसी कार्य योजना बना कर उसे आगे बढ़ाने के किसी गंभीर प्रयास किये जाने की कोई अधिकृत जानकारी कभी नहीं दी गई। सितंबर 2020 में इसका अध्ययन करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड में विचार के लिए लिया भी गया था। इसमें इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा यह बताने के लिए एक प्रस्तुति भी दी गई थी कि राजस्थान चीतों के पुनर्निवास के लिए स्थल और क्षमता दोनों रखता है। राज्य के तत्कालीन वन मंत्री ने भी कहा था कि "कार्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही संस्थान के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा।" मगर जैसा सरकार में होता है कि कुछ फैसले कभी हो ही नहीं पाते।

> **जयपुर में तो रामगंज बाजार के नजदीक 'मौहल्ला चीतावालान' मौजूद है जो गुलाबी नगरी का चीतों के साथ सहकार की याद दिलाता है। भले ही राजस्थान चीतों को बसाने की परियोजना पाने में पिछड़ गया किन्तु हमें इसी पर संतोष करना होगा कि मध्यप्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान इस प्रदेश से सटा हुआ ही है।**

हालांकि भारत की स्थानीय रूप से विलुप्त चीते की सबसे नजदीकी उप-प्रजाति ईरान में पाई जाती है। मगर वहां भी अब इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ईरान से चीतों को भारत लाने का विचार त्यागना पड़ा क्योंकि इस तरह के संरक्षण प्रयासों के दौरान एक महत्वपूर्ण विचार यह भी रहता है कि जहां से जानवरों को उठाकर लाया जाना है वहां उनकी आबादी के अस्तित्व को इस कदम से खतरा नहीं होना चाहिए। दक्षिणी अफ्रीकी के चीते उस प्रजाति के वंशज है जो ईरान में पाए जाते हैं इसलिए उन्हें भारत लाकर यहां बसाने के लिए आदर्श माना गया है। हालांकि अफ्रीका से चीतों को लाकर भारत के जंगलों में छोड़ना एक विवादास्पद प्रयोग भी है जिसे लेकर वैज्ञानिकों और वन्यजीव संरक्षणवादियों में ध्रुवीकरण साफ नज़र नजर आता है। एक वर्ग जो इस प्रयोग से असहमति रखता है वह मानता है कि चीतों का यहां के वनों में स्वच्छंद जीवन संभव नहीं है। अधिक से अधिक यह किया जा सकेगा कि एक बड़े नियंत्रित इलाके में उनके जीवन यापन की हमेशा व्यवस्था की जाती रहे। चीते को पालतू बना कर उनको आखेट में शामिल करने का पुराना मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास रहा है। उस पर अनुसंधान करने वालों का कहना है कि प्रयासों के बाद भी पालतू बनाए गये चीतों की सन्तति नहीं बढ़ी। ऐसे में देखना यह होगा कि स्थान परिवर्तन का अफ्रीका से आए चीतों के प्रजनन व्यवहार पर क्या असर पड़ता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह नई पहल अपने आप में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक वरदान भी हो सकती है। चीते खुले मैदानों में रहते हैं; उनका आवास मुख्य रूप से है वहां है जहां उनके शिकार रहते हैं। घास के मैदान, झाड़ियां और खुली वन प्रणालियां, अर्ध-शुष्क वातावरण और थोड़ा गरम तापमान चीते को माफिक आता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि फिर से बसाये चीतों के लिए न केवल उनके शिकार के आधार को बचाना होगा जिसमें कुछ खतरे वाली प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी निभानी होंगी। यह सुखद बात है कि बड़े मांसाहारियों में चीते का स्वभाव मानव हितों के साथ सबसे कमसंघर्षका है। वे आम तौर पर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और बड़े पशुओं पर भी हमला नहीं करते हैं। इसीलिए इतिहास में हम पाते हैं कि चीतों को पालतू जैसा बना कर शिकार के खेलों में उनका उपयोग किया जाता रहा। अलेक्ज़ेंडर रोजर्स की अनुदित और हेनरी बेवेरिज के संपादन में 1909 में प्रकाशित किताबद तुज़ूक-ए-जहांगीरी ऑर मेमरी ऑफ जहांगीर में यह जिक्र आता है कि मुगल बादशाह अकबर के पास एक हजार चीते थे जिनका इस्तेमाल हिरण और चिंकारा का शिकार करने के लिए किया जाता था। जहांगीर के संस्मरणों की वर्ष 1623 की इस मूल किताब से पता चलता है मुग़ल शासक अपने सूबेदारों को इनाम के तौर पर भी चीते भेंट करते थे। यह भी पहला मौका नहीं है जब चीते बाहर से भारत में लाए गये। इतिहास में दर्ज है कि 1918 से 1945 तक अलग-अलग अवसरों पर कम से कम 200 अफ्रीकी चीतों को भारतीय राजा-महाराजाओं ने शिकार के लिये मंगवाया।

चीता जब भारत में अपनी उपस्थिति पुन: दर्ज़ करा रहा है तब लोग याद कर रहे हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अलवर रियासत के महाराजा ने काबुल से वाजिद खान को चीता पालने के लिए बुलाया था। बाद में जयपुर रियासत में सवाई जगत सिंह के समय उसे जयपुर रियासत के शिकारखाने में नियुक्त किया गया जो चीतों को शिकार करने की ट्रेनिंग दिया करता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राजस्थान में खूब चीते थे मगर सवा सौ साल पहले उनकी नस्ल लुप्त हो गई। सन् 1921 में राजघराने के मेहमान रहे विल फ्रायड के परिवार ने ब्रिटेन से दो चीते समुद्री जहाज से बंबई और वहां से रेल से जयपुर भेजे, जो सन् 1931 तक जीवित रहे। जयपुर में तो रामगंज बाजार के नजदीक 'मौहल्ला चीतावालान' मौजूद है जो गुलाबी नगरी का चीतों के साथ सहकार की याद दिलाता है। भले ही राजस्थान चीतों को बसाने की परियोजना पाने में पिछड़ गया किन्तु हमें इसी पर संतोष करना होगा कि मध्यप्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान इस प्रदेश से सटा हुआ ही है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोडा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राजस्थान में कृषि उच्च शिक्षा गुणवत्ता का स्तर क्या अब कभी सत्तर-अस्सी के दशक के तुल्य पहुँच सकता है?

राजस्थान में कृषि उच्च शिक्षा गुणवत्ता स्तर क्या अब कभी सत्तर-अस्सी के दशक के तुल्य पहुँच सकता है?

लेख का शीर्षक इस बात का द्योतक है कि राजस्थान प्रदेश में कृषि शिक्षा की गुणवत्ता में इतना व्यापक ह्रास हो चुका है कि वर्ष उन्नीस सौ सत्तर-अस्सी के दसक की गुणवत्ता के स्तर पर वापस लौटने को लेखक अन्य उपायों की तुलना में अधिक श्रेयकर मानता है और इसीलिये आकाँक्षा जता रहा है कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के वर्तमान स्तर जो विगत साठ-सत्तर वर्षों में निम्नतम कही जा सकती है, से उबरना कैसे संभव हो सकेगा, इस पर विचार करना ही अब दुष्कर प्रतीत होने लगा है? मूल कारण बिलकुल स्पष्ट है कि गुणवत्ता शिक्षा, जैसी व्यवस्था बनाने में शिक्षण संस्था के प्रबंधकर्ता और उसके शिक्षकों की कड़ी मेहनत और अपेक्षा से कही समय लगता है। शिक्षा के किसी जीर्ण भवन को वित्तीय स्त्रोत उपलब्ध होने पर एक-दो वर्ष में उस भवन का पूर्ण कायाकल्प संभव हो जाता है परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता में विभिन्न कारणों से घटित ह्रास को संस्था और उसके प्रबंधकीय सदस्य अपनी अथक मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से व्यक्तिस: व सामूहिक प्रयासों से दो दशक के समय में भी पुराने स्तर को प्राप्त कर लें तो यह एक बड़ी उपलब्धि और प्रसंशनीय कार्य होगा। क्योंकि ऐसे कार्य में मानवीय पक्ष कही अधिक महत्वपूर्ण है अन्य कारकों की अपेक्षा।

सर्व प्रथम कृषि उच्च शिक्षा जिसके साथ अनुसंधान भी सम्मिलित है, के लिए छात्रों को पढ़ाने वास्ते कक्ष होना इतना आवश्यक नहीं, जितना प्रयोगात्मक परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं और कृषि भूमि, आवश्यक उपकरणों सहित। हमें याद है अपने समय के महान विद्वान रवीन्द्रनाथ जी टैगोर का, शांति निकेतन जिनके पास छात्रों को पढ़ाने के लिए न तो आजकल के सामान कक्ष था और न कोई फर्नीचर। कक्ष के स्थान पर एक बड़े पेड़ की छाया और फर्नीचर की जगह मिट्टी का साफ़ फर्श। भारत के लोग संभवत: उन्हें भूल गए होंगे। भूलना स्वावाभिक है, क्योंकि आज़ादी के बाद हमें वह पढ़ना लाजमी था जिससे हमारी और हमारो की सर्वत्र जय जयकार हो।

केंद्र सरकार को चाहिए कि स्वतंत्र रूप से इस विषय पर एक श्वेत पत्र परिषद् से और स्वतंत्र विचार सभी कृषि वैज्ञानिकों, किसान आयोग के सदस्यों व अन्य विचारकों और सर्वेक्षण से प्राप्त कर व्यापक बहस कर समुचित कदम उठाये। मेरा दृढ़ मत है कि वर्तमान पढ़ाई और अर्जित ज्ञान पूर्व के उन दो सालों के समक्ष कही नहीं टिकता। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली ने एकरूपता और उच्च स्तर का कृषि ज्ञान छात्रों को दिलवाने के लिए पाठ्यक्रम चार वर्ष का तो कर दिया किन्तु विषय वस्तु की वांछित फैकल्टी कही थी ही नहीं, और न ही ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती के लिए कोई ठोस कदम उठाये। साल दर साल अनुभवी अध्यापक अन्यत्र चले गए या रिटायर हो गए और रिक्त हुए पद कभी भरे नहीं जा सके। जिसमे सबसे बड़ी बाधा प्रदेश सरकार उसमे भी विशेष रूप से सचिवालय के बड़े अफसर की लालफीताशाही, संलिप्तता तथा उनके अड़ंगे मुख्य कारक रहे। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों की कभी कोई जवावदेही नहीं रही और न आज है।

कक्षाओं में चूंकि छात्र प्रवेश तो लेते ही हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस विषय/संकाय में वे प्रवेश ले रहे हैं उसके लिए पढ़ाने वाले अनुभवी स्थाई शिक्षक वर्षों से नहीं है। पढ़ाने की जिम्मेदारी कुलपति और महाविद्यालय के डीन पर आ जाती है। महाविद्यालय को जो मिला जैसा भी मिला, उसको कुलपति की सलाह से ठेके पर पढ़ाने के लिए प्रति कालांश के आधार पर रख लिया। और विषय पढ़वाने की प्रक्रिया चलने लगी, दिखावटी तौर पर ही सही। बाहर से सब ठीक ठाक लगता रहा। समय से परीक्षाएं भी होती रही और विद्यार्थी उत्तीर्ण भी होते गए। सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को यह प्रणाली ऐसी भा गयी कि सरकारी बजट बचाने का सूत्र उन्हें हाथ लग गया।

प्रो. (डॉ.) वीर बहादुर सिंह

फलस्वरूप जब कभी विश्वविद्यालय ने भर्तिओं के लिए आदेश मांगे, सरकार के अधिकारी ने उसमे कोई रूचि नहीं दिखाई और मांग को जरूरत से अधिक लंबित रखे रहे ताकि मांग ठंडे बस्ते में डाल दी जाय। नतीजन दशकों से रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई और आज भी 60 प्रतिशत से अधिक पद विषय विशेषज्ञों के प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं और किसी की भी जवावदेही नहीं कि बिना विषय विशेषज्ञों के पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जाती है? जवाव तो मिलता है संबंधित महाविद्यालय के उच्च अधिकारी से कि सभी छात्र अच्छे अंकों से पास होते हैं।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि विश्वविद्यालयों में ठेके पर व्याख्यान कोचिंग संस्थानों सदृश्य ही है। पूर्व में मैं कोचिंग व्यवस्था को अनुचित मानता था परन्तु अब राजकीय संस्थानों की हालत देख मेरा दृष्टिकोण बदल गया है और मेरा अब सरकार को सुझाव है कि व्याख्यान तो किसी कोचिंग वाले से ही दिलवा लें और प्रैक्टिकल के लिए कुछ प्रयोगशालाएं निर्धारित अनुबंध कर प्रैक्टिकल वही से छात्रों को करवाएं। ऐसा करने से सरकार का धन कही अधिक बचेगा, जिसे मुफ्त की रेवड़ी और अन्य ऐसे ही प्रकल्पों में जिनसे पार्टी विशेष का वोट बैंक धनी होता, हो उनमे व्यय कर लिया जाय।

डिग्री तो विश्वविद्यालय देता ही है वह देता रहेगा छात्रों को तो आज डिग्री चाहिए पढ़ने-पढ़ाने से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। डिग्री प्राप्त उपरांत छात्र का अपना भाग्य और स्वयं की राजनीति के अखाड़े में निपुणता। वर्तमान व्यवस्था को सुचारू चलने के लिए कुछ तो हाथ-पैर मारना ही पड़ता है। चाहे कितना ही विरोध हो और अनेक बाधाएँ उत्पन्न की जाय फिर भी जनता को लगना चाहिए कि उनके लाभ के लिए कुछ हो रहा है। कृषि अनुसन्धान परिषद् से सभी प्रकार की निर्भरता समाप्त हो समन्वित अनुसन्धान योजनाएं परिषद् के अपने केंद्रों पर शिफ्ट कर दी जाय। कृषि विश्वविद्यालयों को आत्म निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि संस्था के नाम से शब्द विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी हटा दिए जाये। क्योंकि इन संस्थाओं में अब विश्व स्तर का कुछ है ही नहीं। अत: इन सभी संस्थानों को राज्य महाविद्यालय का नाम देना श्रेयकर होगा। इसलिए कुलपति पद समाप्त कर दिया जाय क्योकि कुलपति ही सभी प्रकार के घोटालों, नियुक्तिओं में, खरीद में, निर्माण आदि कार्यों में व चाटुकारिता में उत्पत्ति केंद्र है। जाति वाद से लेकर अन्य जो अनियमिताएं प्रकाशित होती रही हैं, उन सब में कुलपति सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहते रहे हैं। कृषि शिक्षा व अनुसन्धान में निरन्तर पतन कुलपति की नाकाबिलियत के कारण से है। इसके साथ ही अन्य सभी अधिकारिओं की कत्तर्व्य परायणता और जबाव देहि निश्चित करने की बहुत आवश्यकता है।

निदेशक कृषि राज्य सरकार की अध्यक्षता में प्रबंध मंडल का गठन हो जिसमे राजकीय अधिकारी समेत कुल ग्यारह सदस्य हों एक विधायक, और एक महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य लिए जायँ। प्रत्येक निर्णय की जवाब देही निदेशक की हो। कुलसचिव वरिष्ठ अध्यापकों में से नियुक्त किये जाए और वित्त नियंत्रक चयन प्रक्रिया से राज्य आयोग नियुक्त करे। अध्यापकों व अन्य कर्मचारिओं के समयबद्ध तरक्की पर रोक लगे। इन कदमों से चाटुकारिता पर अंकुश लगेगी और कर्तव्य परायणता बढ़ेगी।

मुझे आश्चर्य है कि अभी तक छात्र या उनके अभिभावक विश्व विद्यालय की प्रति वर्ष की धोकेबाजी के विरुद्ध न्यायलय कियों नहीं गए? एक बार सैद्धांतिक तौर पर यदि इस प्रकरण पर सहमति बनती है तो मैं फिर और सुझाव प्रेषित कर सकता हूँ। जिसमे कृषि शिक्षा के प्राइवेट करने पर भी एक विकल्प हो सकता है। कुछ भी हो भावी पीढ़ियां कृषि में अभी अशिक्षितों से भी निम्नतर पैदा हो रही हैं। अशिक्षित मज़दूरी से जीवन तो काट लेगा लेकिन ये तथाकथित शिक्षित मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे।

–प्रो. (डॉ.) वीर बहाद सिंह,
पूर्व कुलपति एवं डेरी खाद्य विज्ञ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

डीएपी व यूरिया के लिए किसान उमड़े

मालपुरा,(निसं)। दो महिनों के लम्बे समय बाद मंगलवार को केवीएसएस मालपुरा पर खाद आने की मिली सुचना पर हजारों किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। खाद लेने आये किसानों की लगी लम्बी कतारों में शामिल किसान 2 से 3 घंटे की कडी मशक्कत के बाद काउंटर पर तो पहुंचे लेकिन स्टॉक खत्म हो जाने के चलते बिना खाद के ही किसान निराश होकर लौट गये। दस हजार से अधिक यूरिया बैग की डिमांड के बावजूद केवीएसएस को महज 507 कट्टों का स्टॉक मिलने से व्यवस्थाएं चरमरा गई। खाद का स्टॉक खत्म होने की सूचना के साथ ही परिसर में एकाएक भगदड सी मच गई। इतनी बडी संख्या मे किसानों की भीड के बावजूद प्रबंधकों द्वारा ना तो छाया पानी की व्यवस्थाएं की गई और ना ही पुलिस जाप्ता लगाया गया।

महिला शौचालय में आठ माह का भ्रूण मिला

देवगढ़ ,(निसं)। देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के महिला शौचालय में करीब 8 माह का परिपक्व नर भ्रूण मिलने से हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मचा गया। आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम करवाया।

जानकारी के अनुसार देवगढ़ के सरकारी अस्पताल में सुबह के वक्त जब सफाई कर्मचारी शौचालय की सफाई करने जा रहे थे, इस दौरान उन्हें महिला शौचालय में भ्रूण पड़ा मिला। यह भ्रूण करीब 8 माह का बताया जा रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार रात को किसी ने यह भ्रूण शौचालय में फेंका होगा। भ्रूण किसने फेंका है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।

- **देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के महिला शौचालय की घटना**

सीएचसी प्रभारी डॉ. अनुराग शर्मा ने इसकी जानकारी देवगढ़ थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत को दी जिस पर उन्होंने एएसआई गिरधारी सिंह मय जाप्ता को मौके पर भेजा। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की एवं पोस्टमार्टम करवाने के लिए मोर्चरी में रखवाया ओर पोस्टमार्टम कराया जिसमे पता चला कि यह नर भ्रूण है।

सीएचसी प्रभारी डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि सुबह के वक्त जब सफाई कर्मचारी शौचालय की सफाई कर रहे थे, उसी वक्त यह भ्रूण मिला है। देखने मे यह भ्रूण लगभग 8 माह का लग रहा था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी है, फिलहाल भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमे पता चला कि यह भ्रूण नर का है। साथ ही हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे खंगालकर किसके द्वारा इस भ्रुण को यहां डाला गया इसका पता लगाया जाएगा, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

कचरे के ढेर में पांच माह का भ्रूण मिला

डूंगरपुर, (निसं)। शहर के प्रतापनगर कॉलोनी में एक 5 महीने का भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड जमा हो गई। जिसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को जब्त कर मोर्चरी में रखवाया है और भ्रूण फैंकने वाली महिला की तलाश शुरू कर रही है। अस्पताल चौकी के कॉन्स्टेबल ईश्वरलाल ने बताया कि प्रतापनगर कॉलोनी से रेलवे की ओर जाने वाले कुछ लोगों ने मंगलवार सुबह कचरे के ढे र में एक बच्चे को देखा। जिसके बाद मौके पर भारी भीड जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। लेकिन भ्रुण को फेंककर जाने वाले के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी।

चीतों के भोजन के लिए चीतलों को अन्य क्षेत्रों से लाने की बात तथ्यहीन

गत 17 सितम्बर, 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा नामीबिया से लाये गये चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। देश में चीता विलुप्त होने के 75 वर्ष के बाद पुन: स्थापित करने के उद्देश्य से चीता लाये गये हैं, यह देश एवं प्रदेश के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कतिपय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में इस आशय के समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं कि चीतों के भोजन हेतु चीतलों को अन्य क्षेत्रों से लाया जाकर कूनों राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जा रहा है। कुछ समाचार पत्रों में तो राजस्थान से चीतल लाये जाने के भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न समाचार माध्यमों तथा सोशल मीडिया में फैल रही इस खबर में कोई सत्यता नहीं है। राजस्थान से कोई चीतल मध्यप्रदेश नहीं लाया गया है। अंतर्राज्यीय वन्यप्राणियों के स्थानान्तरण के लिए भारत सरकार एवं दोनों राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, अत: राजस्थान से चीतल लाये जाने की पुष्टि राजस्थान सरकार की सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। कूनों राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में 20,000 से अधिक चीतल मौजूद हैं । ऐसे में चीतों के भोजन के लिये अन्यत्र से चीतल लाकर छोड़ा जाना एक कल्पना मात्र है। वस्तुत: चीता लाये जाने के उपरांत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कोई चीतल लाकर नहीं छोड़े गये हैं।

- **कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाये गये चीतों की स्थापना**

मध्यप्रदेश में वर्ष 2015 से लगातार सक्रिय वन्यप्राणी प्रबंधन किया जा रहा है। प्रदेश में की राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य ऐसे हैं जहां चीतलों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है जिससे गर्मियों में चारा की समस्या उत्पन्न होती है।

अत: ऐसे जगहों से चीतलों को ऐसे राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में छोड़ा जाता है जहां इनके चारे की पर्याप्त उपलब्धता होती है। इसके तहत पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तथा नरसिंहपुर अभयारण्य से चीतलों को निकालकर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कूनों राष्ट्रीय उद्यान तथा नौरादेही अभयारण्य में भेजे गये हैं। यह सही नहीं है कि केवल राष्ट्रीय उद्यान पार्क में ही चीतलों को छोड़ा गया है। प्रदेश में अब तक 6000 से अधिक चीतल एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़े जा चुके हैं। इसके मुख्य उद्देश्य शाकाहारी वन्यप्राणियों में अनुवाशिंक समस्याओं को दूर करना, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में फसल की नुकसानी कम करने तथा गांवों के द्वारा रिक्त किये गये स्थलों पर समुचित वन्यप्राणियों की संख्या स्थापित करना है। प्रदेश के अनेक राष्ट्रीय उद्यान जैसे बांधवगढ़ , कान्हा तथा पेंच में काफी संख्या में चीतल पाये जाते हैं जिसके कारण वहां का पर्यावास भी प्रभावित होता है। पर्यावास को बचाये रखने के लिये भी यह आवश्यक है कि वन्यप्राणियों के अत्यधिक जैविक दबाव को कम किया जाये। इस कार्य को इन वन्यप्राणियों को अन्यत्र छोड़े जाने से ही सम्पन्न किया जा सकता है। वर्तमान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 30,000 से अधिक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 50,000 से अधिक तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 30,000 से अधिक चीतल मौजूद है जबकि क्षेत्रफल में अधिक होने के बावजूद सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 10,000 चीतल उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान तथा नौरादेही अभयारण्य जो कम घनत्व के संरक्षित क्षेत्र है वहां शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या को बढ़ ाने के उद्देश्य से कान्हा, बांधवगढ़ तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से शाकाहारी वन्यप्राणियों को छोड़ा जा रहा है। मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों का उच्च कोटि का प्रबंधन किया जा रहा है तथा ऐसा कोई कृत्य न तो किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा जिससे विश्नोई समाज, जो वन्यप्राणी संरक्षण में अपने योगदान के लिये विश्व विख्यात है, की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यहां यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विश्नोई समाज की अमृता देवी के नाम पर वन्यप्राणी संरक्षण में उच्च कोटि का योगदान देने के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं।

प्रारुप प्रमुख सचिव,
वन द्वारा अनुमोदित
(जसवीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी), म.प्र.

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 21 सितम्बर, 2022

आश्विनी मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, पुषय नक्षत्र रात्रि 11:47 तक, परिद्य योग प्रात: 9:12 तक, बव करण दिन 10:31 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-सिंह, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग रात्रि 11:35 से रात्रि 11:47 तक है। आज इन्दिरा एकादशी व्रत है और एकादशी का श्राद्ध और आखिरी चाहर शम्बा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:19 तक, शुभ 10:50 से 12: 20 तक, चर 3:21 से 4:21 तक, लाभ 4:51 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:18, सूर्यास्त 6:22

मेष

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। मन में असंतोष और भय बना रहेगा।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

मकर

परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा।

मीन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।